

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय अनुभाग -2

देहरादून, दिनांक 13 जुलाई, 2010

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, अन्य मा0 उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकरणों इत्यादि में विचाराधीन वाद/रिट याचिकायें/अपील इत्यादि में राज्य की ओर से पैरवी किया जाना और इस सम्बन्ध में मासिक सूचना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय/महोदया,

मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, अन्य मा0 उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकरणों इत्यादि में वर्तमान में कतिपय वाद/रिट याचिकायें/अपीलें इत्यादि विचाराधीन हैं, जिनमें एक पक्ष राज्य सरकार है। उक्त मा0 न्यायालयों में राज्य की ओर से वाद/अपील/रिट याचिकायें योजित करने हेतु शासन के प्रशासकीय विभागों को न्याय विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है और उक्त के पश्चात न्यायालय प्रकरणों में राज्य की ओर से प्रशासकीय विभागों द्वारा पैरवी की जाती है।

2- इस विषय में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मा0 न्यायालयों में विचाराधीन उक्त वादों में राज्य की ओर से समुचित पैरवी नहीं की जाती है जिस कारण राज्यहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। कुछ मामलों में प्रशासकीय विभागों/ उनके अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उचित पैरवी नहीं की जाती है तो कई मामलों में राज्य द्वारा आबद्ध अधिवक्ताओं द्वारा उक्त न्यायिक प्रकरणों में राज्य का पक्ष मा0 न्यायालय के सम्मुख समुचित रूप से नहीं रखा जाता है। इस कारण राज्य का पक्ष विधिक दृष्टि से मजबूत होने के उपरान्त भी अधिकांश वादों में राज्य की ओर से समुचित पैरवी न होने के कारण राज्य के विरुद्ध निर्णय पारित हो जाते हैं जो गम्भीर विषय है।

3- वर्तमान में प्रशासकीय विभागों द्वारा उन न्यायालय प्रकरणों जिनमें एक पक्ष राज्य सरकार है और जिनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की जा रही है, के विषय में कोई मासिक सूचना न्याय विभाग में उपलब्ध नहीं करायी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है और यह आवश्यक है कि प्रशासकीय विभागों से प्राप्त उक्त मासिक सूचनाओं को न्याय विभाग में संकलित किया जाय ताकि न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह न्याय विभाग में समीक्षा की सके।

4- उक्त के दृष्टिगत, इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायालय प्रकरणों में राज्य सरकार का पक्ष सुदृढ़ बनाये जाने और उक्त विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना न्याय विभाग में संकलित किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाय:-

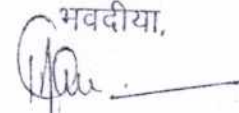
(1) शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित न्यायालय प्रकरणों में राज्य की ओर से समुचित पैरवी की जाय ताकि राज्यहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों और राज्य के विरुद्ध पारित होने वाले निर्णयों से बचा जा सकें।

(2) उक्त हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा मा० न्यायालयों में अपने विभाग से सम्बन्धित विचाराधीन न्यायालय प्रकरणों में राज्य की ओर से समुचित पैरवी सुनिश्चित कराये जाने हेतु एक सक्षम अधिकारी, जो शासन के संयुक्त सचिव स्तर से निम्न का न हो, नामित किया जाय जिनका यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रकरणों में उनके विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राज्य की ओर से समुचित पैरवी की जाय। उक्त नामित अधिकारी यह भी देखेंगे कि न्यायालय प्रकरणों में शासन द्वारा आवद्ध अधिवक्ता द्वारा राज्य की ओर से समुचित पैरवी की जा रही है और मा० न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष रखा जा रहा है। यदि प्रशासकीय विभाग के उक्त अधिकारी का यह मत हो कि उनके विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा न्यायालय प्रकरण में राज्य की ओर से उचित पैरवी नहीं की जा रही है तो वह इस तथ्य को विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के संज्ञान में लायेंगे जिनके द्वारा उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जायेगा। यदि शासन द्वारा आवद्ध अधिवक्ता द्वारा



न्यायालय प्रकरण में राज्य की ओर से समुचित पैरवी न की जा रही हो, राज्य का पक्ष न रखा जा रहा हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा यह तथ्य न्याय विभाग के संज्ञान में लाया जायेगा और तदोपरान्त न्याय विभाग द्वारा ऐसे अधिवक्ता की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा।

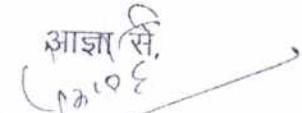
(3) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त न्यायालय प्रकरणों की एक मासिक सूचना जो संलग्न प्ररूपों में होगी, प्रत्येक माह की दस तारीख या उससे पूर्व न्याय विभाग को उपलब्ध करायी जाय। प्रशासकीय विभागों से प्राप्त उक्त सूचनाओं को न्याय विभाग में सकलित किया जायेगा और न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह न्याय विभाग द्वारा समीक्षा की जायेगी।

भवदीया,  
  
(श्रीमती इन्दिरा आशीष)  
प्रमुख सचिव,  
तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या- 1160/XXXVI(2)/10

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
- 7- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0

आज्ञा सि,  
  
(प्रेम सिंह खिमाल)  
अपर सचिव,

प्ररूप-1

भाग 10 उच्चतम न्यायालय में लखित वादों से सम्बन्धित विवरण

माह-

| 1           | 2                            | 3  | 4   | 5  | 6       |
|-------------|------------------------------|--|---|--|---------|
| क्रम संख्या | माह के अन्त में कुल लखित वाद | माह में राज्य के पक्ष में निर्णीत वादों की संख्या, अधिवक्ता नाम जिसके द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की गयी | माह में राज्य के विरुद्ध निर्णीत वादों की संख्या, अधिवक्ता नाम जिसके द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की गयी | यदि निर्णय राज्य के विरुद्ध हुआ हो तो प्रोविडो का मत | टिप्पणी |
|             |                              |  |   |  |         |
|             |                              |  |   |  |         |

प्ररूप-2

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं अन्य मा0 उच्च न्यायालयों में लभित वारों से सम्बन्धित विवरण  
विभाग का नाम-  
माह-

| 1         | 2                            | 3   | 4  | 5  | 6       |
|-----------|------------------------------|---|--|--|---------|
| कम संख्या | माह के अन्त में कुल लभित वार | माह में राज्य के पक्ष में निर्णीत वारों की संख्या, अधिवक्ता का नाम जिसके द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की गयी | माह में राज्य के विरुद्ध निर्णीत वारों की संख्या, अधिवक्ता का नाम जिसके द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की गयी | यदि निर्णय राज्य के विरुद्ध हुआ हो तो प्रवि0 का मत | टिप्पणी |
|           |                              |   |  |  |         |
|           |                              |   |  |  |         |

प्ररुप-3

अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक अधिकरणों इत्यादि में ललबित वादों से सम्बन्धित विवरण

माह-

| 1              | 2                                   | 3  | 4   | 5  | 6       |
|----------------|-------------------------------------|--|---|--|---------|
| क्रम<br>संख्या | माह के अन्त<br>में कुल ललबित<br>वाद | माह में राज्य के पक्ष<br>में निर्णीत वादों की<br>संख्या, अधिवक्ता का<br>नाम जिसके द्वारा<br>राज्य की ओर से<br>पैरवी की गयी | माह में राज्य के विरुद्ध<br>निर्णीत वादों की<br>संख्या, अधिवक्ता का<br>नाम जिसके द्वारा राज्य<br>की ओर से पैरवी की<br>गयी | यदि निर्णय राज्य के<br>विरुद्ध हुआ हो तो<br>प्रतिवि० का मत | टिप्पणी |
|                |                                     |  |   |  |         |
|                |                                     |  |   |  |         |